design and alignment of the Tunnel, a programme for building the tunnel, types of equipments to be used, the cost estimates etc. The salient features of the proposed tunnel are as follows:

Length	:	About 9 KM.
Width	:	2 lane carriage way of 8 metres width, foot path on both sides.
Designed traffic density	:	282.50 passenger car unit per hour.
Proposed method of Construction	:	Drill & Blast.
Preliminary cost	:	Rs. 603.02 crores including FE Component of Rs. 103.06 crores (at 1996 prices) excluding the cost of land acquisition, approach roads, bridges and retaining structures.
Periqd of construction	:	9 years after start of actual construction.

मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या

*446. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज औरतन कितने व्यक्तियों को सेवा प्रदान कर रहा है,

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय औसत संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त राज्यों में सभी एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा संचार मंत्री): (क) और (ख) प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा जितने उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है उनकी औसता संख्या इस प्रकार है:-

मध्य प्रदेश	260
असम	418
राजस्थान	412
राष्ट्रीय औसत	655

(ग) विभित्र क्षेत्रों में पंजीकृत मांग के आधार पर नए एक्सचेंज खोले जाते हैं या मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार किया जाता है।

भारत में परिवहन-विकास के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

*447. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल-भूतल परिहवन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सह सच है कि विश्व बैंक के लेखापरीक्षा (ऑडिट) मिशन ने हाल ही में प्रकाशित हुई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में परिवहन विकास संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन न केवल धीमा है बल्कि असंतोषजनक भी है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या यह सच है कि मिशन ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वसन में अनेक खामियां होने का भी उल्लेख किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी वेकटरामन): (क) से (घ) विश्व बैंक का लेखा परीक्षा मिशन ऐसे विभिन्न मुद्दों के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, संविदाकारी उद्योग और परामर्शदाताओं के साथ परामर्श करता रहा है जिनके कारण राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है। पत्पश्चात बैंक, उनकी ऋण (विश्व बैंक) सहायता प्राप्त भावी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसे वि विलम्ब को कम करने के लिए सरकार को उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना चाहता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

अभी सरकार की प्रतिक्रिया नहीं बतालाई जा सकती।

सरकारी कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर

*448. **श्री ईशदत्त यादव:**

श्री नागमणि:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर खरीदना अनिवार्य है, और